<xiii) Western Paques (India) Ltd. has signed an MOU with Ho Chj Minh and Hanoi Municiple Corporation Vietnam to process municiple solid waste to solve long unresolved, environmental hazard of. waste .disposal problem of. Ho Chi Minh city and produce energy and manure as a by-product. Western Paques have also signed MOUs with the Municipal Corporation of Ankara City (Turkey), Istanbul City (Turkey) and Chiang Mai city (Thailand).

(xiv) MOU between M|s. Thermochem Inc., California, USA and M|s. Ajinkyatara Cooperative Sugar Mills, Maharashtra for a 10 MW Power Project through bagasse gasification.

(xv) MOU between M/s. CTBR, France and M|s. Esquire Energy Ltd., Bombay for projects in sugar mills for bagasse cogeneration.

(xvi) A technical collaboration venture between Tata BP Solar (Pvt.) Ltd., Bangalore and BP Solar UK foor manufacturing solar photovoltaic modules and systems with an installed capacity of 1 MW per year has been set. up at Electronic City, Bangalore.

(xvii) M|s. Webel-SL Energy Systems, West Bengal" and' Helios of Italy are setting up a project if or manufacturing, of solar cells, photovoltaic modules and systems.

(xviii) M|s. Eco Solar, Pune is working with University of Colo rado, USA for developing Cadmium Telluride-based Photovoltaic Mo dules with an annual capacity of 700 KW.....

(xix) M|s. Sun Source Cannon Energy Ltd., India and M|s. Ca'nan Power Corpn., USA are'setting up a joint venture at a total cost of Rs. 60 crores for alternate energy project like solar, wind etc. in India,

(xx) M|s. Owimax Services India Ltd. and M|s. Owimax of Russia are setting up a joint venture for providing services in India in the field of photovoltaics, semiconductors, non-conventional energy soruces and pollution control.

(xxi) M|s. Peerless Developers Ltd., Calcutta and M|s. Frazer Nash Research Ltd., U.K. are starting a joint venture for manufacture of solar passenger transport vehicles powered by batteries, supplemented by photovoltaic charging.

पदाधिकारियों के विरुद्ध गठित किए गए जांच आयोग

1452. **श्री नागमणि :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों के दौरान सार्वजनिक जीवन में कार्यरत शीर्ष पदाधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने, विभिन्न सरकारी विभागों, कार्यक्रमों इत्यादि में दोषों और कमियों की जांच करने और इनमें सुधार करने हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से कुल कितने आयोग कब-कब और किन-किन मामलों में गठित किए गए थे ;

(ख) कितने आयोगों की सिफारिशों पर समुचित कार्यवाही पूरी की गई है और कितने आयोगों की सिफारिशों पर आंशिक रूप से कार्यवाही की गई है और कितने आयोगों की सिफारिशों पर कार्यवाही अभी भी लम्बित है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे आयोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है अथवा तैयार किए जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) (क) इस मंत्रालय ने पिछले 10 वर्षों में किसी भी शीर्ष पदाधिकारी

के विरुद्ध कोई भी जांच आयोग स्थापित नहीं किया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Corporation cases against Government officials registered by OBI

4453 SHRI KRISHNA KUMAR. BIRLA: Will the PRIME MINISTER bo pleased to state:

(a) whether the CBI has register ed cases of corruption against Seve. ral Government officials during the iiree months;

(b) if so, the details thereof and the charges registered against them; and

(c) what punitive action Government propose.to take against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PEN- SIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir.

(fo) 323 cases of corruption re registered against 571 Govt, officials during the last 3 months i.e. August to October, 1994, Out of 323- cases, investigation in 60, cases has so far been finalised. Out of 60 cases finalised, 30 cases were sent, uP *f°** trial. 29 cases were referred to the Deptts, concerned for initiating Regular De, partmental Action and one case was closed for want of-sufficient evidence,

(c) Action against such officers! depends on the outcome of judicial trials arid|o$_r$ regular department actio^ which are quasi-judicial in nature.

कापार्ट द्वारा बिहार में स्वीकृत की गई योजनायें

1454. **श्री रामदेव भंडारी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1994 से अब तक कापार्ट द्वारा मधुबनी (बिहार) में स्वयंसेवी संस्थाओं को स्वीकृत की गई योजनाओं और जारी की गई धनराशि का ब्योरा क्या-क्या है और योजनाओं के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) किन-किन संस्थाओं के विरुद्ध धनराशि के दुर्विनियोग की जांच चल रही है ; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उलमभाई पटेल) :(क) बिहार के मधुबनी जिले में कापार्ट द्वारा 1.4.1994 से 31.10.1994 तक स्वयंसेवी संस्थाओं को दी गई सहायता, स्वीकृत की गई योजनाएं, स्वीकृत की गई धनराशि एवं जारी की गई धनराशि एवं स्वीकृत योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) बिहार के मधुबनी जिले में कापार्ट द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी स्वयंसेवी संस्था के विरुद्ध धनराशि के दुर्विनियोग के लिए पूछताछ का कोई मामला लंबित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।